तिब्बत देश

चीन की नई भाषा नीति – उपनिवेशवाद फिर बेनकाब

तिब्बत इन दिनों प्रदर्शनों के एक ऐसे दौर में से गुजर रहा है जो चीनी शासकों के लिए एक अभूतपूर्व दर्द सिद्ध हो रहा है। वहां के उत्तर–पूर्वी प्रांत आम्दो (चीनी नाम 'चिंघाई') के सैकेंडरी और मिडल स्कूलों के बच्चे आए दिन क्लास में या बस्ती के मुख्य चौराहे के बीचों–बीच हाथ से लिखे पोस्टर, बैनर या तिब्बती झंडा लेकर तिब्बती भाषा में नारे लगाते हैं। देखते ही देखते चीनी पुलिस के जासूस और उनके बाद वर्दीधारी पुलिस और सेना से लदी हुई गाड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और पकड़कर पुलिस थाने में ले जाती हैं। छात्रों की एकमात्र मांग यही होती है कि हमें हमारी तिब्बती भाषा में पढ़ने दिया जाए और चीनी भाषा को जबरन स्कूल की मुख्य भाषा बनाने की नई नीति को वापस लिया जाए।

1951 से तिब्बत पर जबरन कब्जा करके बैठा हुआ चीनी तंत्र तिब्बत में आजादी की मांग करने वाले आंदोलन को कुचलने और प्रदर्शनों पर काबू पाने में अच्छी खासी महारत हासिल कर चुका है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि उनका सामना स्कूली बच्चों से हो रहा है। जब तक चीनी पुलिस और सेना प्रदर्शनकारी बच्चों पर काबू पाते हैं तब तब वे अपनी बात कह चुके होते हैं। बच्चों को 'गिरफ्तार' करने में बच्चों से ज्यादा फजीहत पुलिसतंत्र और चीन सरकार की हो रही है।

इन प्रदर्शनों का सिलसिला पिछले अक्तूबर से चल रहा है और चिंघाई के सभी छह तिब्बती ऑटोनामस प्रिफेक्चरों में फैलने के बाद अब यह कुछ बदले हुए रूप में पड़ोसी सिचुआन के खंपा तिब्बती क्षेत्रों में भी फैल रहा है। प्रदर्शनों के केंद्र में वहां की अल्संख्यक राष्ट्रीयताओं के लिए चलाए जाने वाले वे चीनी सरकारी 'मिंझू' स्कूल हैं जो तिब्बती, मंगोल और उइगुर (तुर्की) बहुल इलाकों में स्थापित किए गए हैं। प्रांत सरकार की इस नीति के खिलाफ पहला बड़ा प्रदर्शन अक्तूबर में बीजिंग के मिंजू विश्वविद्यालय में हुआ था जिसमें सैंकड़ों तिब्बती छात्रों ने जलूस निकाल कर इस नीति को वापस लेने की मांग की थी।

पिछले साठ साल से इन स्कूलों में प्राइमरी और मिडल स्तर तक उनकी अपनी भाषाओं में पढ़ाई की जाती थी। चीनी मंडारिन भाषा को पढ़ाई का माध्यम केवल सैकेंडरी और विश्वविद्यालय में बनाया जाता रहा है। लेकिन 2008 में तिब्बत और 2009 में शिंजियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) में हुए चीन विरोधी प्रदर्शनों के बाद चीनी शासकों ने एक नई रणनीति तैयार की है। इन प्रदर्शनों के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार लंबे विश्लेषण के बाद इस नतीजे पर पहुंची हैं कि साठ साल तक चीन का हिस्सा बनने के बाद भी तिब्बत, शिंजियांग और भीतरी मंगोलिया के लोगों में चीन के प्रति 'देशभक्ति' की कमी है। इसका असली कारण यह है कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान और भाषा से जुड़े रहने के 'पिछड़ेपन' को छोड़ नहीं पाए हैं। लिहाजा इन कब्जाए हुए प्रांतों की जनता को 'देशभक्त' बनाने के लिए यह नई भाषा नीति लागू की जा रही है।

इन इलाकों में चीनी 'देशभक्ति' को बढ़ावा देने के लिए पिछले साठ साल से वहां धार्मिक संस्थानों को नष्ट करने, व्यक्तिगत धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने, भिक्षुओं को मठों से निकाल कर बरसों तक श्रम शिविरों में रहने की सजा देने, धर्म की शिक्षा और प्रचार पर प्रतिबंध लगाने और तिब्बती मठों में भिक्षुओं और भिक्षुणियों को जबरन 'देशभक्ति–शिक्षा' वाले राजनीति प्रशिक्षण और परीक्षाओं में पास होने जैसे कदम उठाए जा चुके हैं। इन प्रयासों की असफलता के बाद भी चीन सरकार की नई भाषा नीति केवल यही दिखाती है कि चीनी शासक आज तक इस बात को समझ नहीं पाए कि किसी समाज की पहचान को छीन कर उसका दिल नहीं जीता जा सकता।

इस नई नीति का मुख्य नारा है, ''मंडारिन भाषा पहले, तिब्बती बाद में। देशभक्त बनने के लिए हर नागरिक की पहली भाषा मंडारिन होनी चाहिए।'' यहां यह जानना रोचक होगा कि तिब्बती प्रदर्शनों से ठीक दो महीने पहले अगस्त में चीन के गुआंगझाउ (कैंटन) प्रांत में कैंटनी भाषा को जिंदा रखने के लिए भी मंडारिन विरोधी प्रदर्शन भी हो चुके हैं। कैंटनी चीनी भाषा का एक मुख्य रूप है और कम्युनिस्ट शासन द्वारा मंडारिन थोपने से पहले यह सदियों से चीन में लोकप्रिय रही है।

पिछले दिनों एक भारतीय टीवी में अपनी भेंटवार्ता के दौरान तिब्बत के निर्वासित शासक और धार्मिक नेता दलाई लामा ने चीन की इस नई भाषा नीति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे साठ वाले दशक की भयावह 'सांस्कृति क्रांति' का एक नया रूप बताया था। तिब्बत में पिछले कुछ साल से तिब्बती विरोध का प्रतीक बनकर उभरने वाली एक लोकप्रिय तिब्बती लेखिका सुश्री वोज़ेर ने चिंघाई सरकार की इस नई भाषा नीति की कड़ी आलोचना करने हुए एक लेख लिखा है जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद इन दिनों इंटरनेट पर उपलब्ध है। अपने इस लेख में उन्होंने कहा है कि 2008 के तिब्बती प्रदर्शनों से घबराई हुई चीन सरकार अब तिब्बती जनता के साथ आर–पार की लड़ाई पर उतर आई है। उसे यह लगने लगा है कि तिब्बती भाषा और उसकी पढ़ाई को खत्म करके वह समस्या के असली स्रोत को बंद कर देगी और तिब्बती समस्या का स्थायी हल निकाल लेगी।

रोचक बात यह है कि चीनी सरकार की चिंता का केंद्र बने चिंघाई और खम प्रांतो के ये ऐसे इलाके हैं जिन्हें चीन सरकार तिब्बत का हिस्सा ही नहीं मानती। सवाल उठता है कि अगर 'गैर तिब्बती' क्षेत्रों में चीनी कब्जे के खिलाफ ऐसा जनविरोध है तो 'असली' तिब्बत की जनता खुद को किस हद तक 'चीनी' नागरिक मानती होगी? चीन की इस नई भाषा नीति ने चीन सरकार के उपनिवेशवादी चेहरे को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है।

– विजय क्रान्ति

भाषा को लेकर तिब्बत के सेरशुल काउंटी में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ

(टिबेट टाइम्स ऑनलाइन, 9 नवंबर)

गत 8 नवंबर को 700 से ज्यादा भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने 'समानता' एवं 'भाषा की आज़ादी' को लेकर सेरशुल काउंटी के केंद्र तक मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें ज़ाछुका कस्बे में ही रोक दिया। इनमें से ज्यादातर भिक्षु कार्जे प्रशासनिक क्षेत्र के सेरशुल काउंटी के सेरशुल मठ के थे। पढ़ाई का माध्यम अनिवार्य रूप से चीनी भाषा को बनाने के विरोध में इसके पहले अक्टूबर माह में क्विंघई प्रांत में हजारों तिब्बती स्कूली छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद 7 नवंबर को हुए एक विरोध प्रदर्शन में 50 भिक्षु एवं भिक्षुणी शामिल हुए, इन सबकी यह मांग थी कि चीन सरकार तिब्बती जनता की भाषा का सम्मान करे। इसी क्षेत्र में एक तीसरा विरोध प्रदर्शन भी हुआ जिसमें बुम निंगदे के दो मठों के करीब 300 भिक्षु एवं भिक्षुणियों के साथ कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। यह प्रदर्शन 26 अक्टूबर को हुई एक घटना से भड़क गए थे जिसमें कुछ चीनी अधिकारी सेरशुल काउंटी में आए थे, उनके पास 'ड्रक के' बोलने वाले लोगों से वसूले गए जुर्माने के जब्त किए गए बक्से थे। ड्रक के का मतलब है तिब्बती भाषा में बातचीत के दौरान चीनी शब्दों, पदों और वाक्यों को ठूंसना। अधिकारियों का कहना है कि इस चलन को बंद करना होगा। लेकिन भिक्षुओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक स्वैच्छिक प्रयास है और किसी को भी इसके लिए मजबूर नहीं किया जाता।

तिब्बती पर्यवेक्षकों और चीनी एवं कई विदेशी पारिस्थिति की विदों का कहना है कि इन लोगों को नए जगहों पर बसाने से उनकी गरीबी बढ़ सकती है, परिवार टूट सकते हैं और एक बाड़े के भीतर पशुओं द्वारा बहुत ज्यादा चराई करने से मिट्टी में क्षरण को बढ़ावा मिल सकता है।

चीनी प्रवासियों के लिए बनाए जाएंगे सस्ते अपार्टमेंट

(टिबेटन रीव्यू डॉट नेट, 11 नवंबर)

चीन सरकार ने 9 नवंबर को कहा है कि वह 12वीं पंचवर्षीय योजना (2011–2015) के दौरान तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में करीब 20,000 अपार्टमेंट बनाएगी ताकि वहां रहने वाले चीनी प्रवासी श्रमिकों और स्थानीय मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के शहरी लोगों के आवास की समस्या का समाधान हो सके। इस परियोजना के तहत वे लोग आवेदन कर सकेंगे जो निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के शहरी नागरिक या चीनी प्रवासी श्रमिक हों और वे निम्न शर्तों को पूरा करते हों: उनके पास जन सुरक्षा के क्षेत्रीय ब्यूरो द्वारा जारी शहरी हुको यानी स्थानीय निवास प्रमाणपत्र हो, तिब्बत में एक साल से ज्यादा समय से रह रहे हों, किराया चुका सकने लायक स्थिर आय हो, उनकी वार्षिक या मासिक पारिवारिक आय मानक प्रति व्यक्ति खर्च करने योग्य आय से कम हो, उनके पास निजी संपत्ति या प्रति व्यक्ति रहने की जगह 15 वर्ग मीटर से कम हो और उन्हें किसी स्थानीय हाउसिंग बीमा नीति का लाभ मिला हुआ हो।

ऐसा लगता है कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ चीनी प्रवासियों को ही मिलेगा क्योंकि उनके प्रशासन के लोगों से व्यक्तिगत संपर्क हैं जिसमें कि ज्यादातर चीनी ही हैं।

चीन में एक विवादास्पद कार्यक्रम के तहत 6000 तिब्बती खानाबदोशों को नई जगहों पर बसाया गया

(फायूल, 29 नवंबर)

चीन सरकार ने कहा है कि उसने यून्नान प्रांत के डेचेन प्रशासनिक क्षेत्र के शांग्री–ला (तिब्बती में ग्यालथांग) काउंटी में रहने वाले 1300 खानाबदोश परिवारों के 6000 तिब्बती चरवाहों को एक सरकारी कार्यक्रम के तहत स्थायी मकानों में जाने में मदद की है। चीन की सरकारी मीडिया में यह खबर आई है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह काफी विवादास्पद तरीका है और इसमें लोगों के अधिकारों का जमकर उल्लंघन हुआ है। चीन के ऑनलाइन टिबेट न्यूज सर्विस के अनुसार साल 2009–10 के दौरान तथाकथित शांग्री–ला काउंटी में 2,135 मकान बनाए गए हैं। एक साल के भीतर 1,300 परिवारों के 6,000 तिब्बती खानाबदोश चरवाहों को स्थायी मकानों में बसाने के इस कार्यक्रम में 111,780,900 युआन खर्च किए जाएंगे। शांग्री–ला को तिब्बत में परंपरागत रूप से ग्यालथांग के नाम से जाना जाता है। चीन सरकार ने भी पहले इसका नाम

जोंगडियन काउंटी रखा था। लेकिन इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीनी अधिकारियों ने साल 2001 में इसका नाम बदलकर 1933 में जेम्स हिल्टन द्वारा लिखे उपन्यास लॉस्ट होरिजन की काल्पनिक भूमि शांग्री–ला के नाम पर रख दिया। तिब्बती खानाबदोशों और चरवाहों को तथाकथित 'आधुनिक रहन–सहन व्यवस्था' के तहत कॉन्क्रीट की इमारतों में बसा देने की चीन सरकार की इस नीति पर मानवाधिकार संगठनों और तिब्बती पर्यवेक्षकों ने सवाल उठाए हैं। तिब्बती पर्यवेक्षकों और चीनी एवं कई विदेशी पारिस्थिति की विदों का कहना है कि इन लोगों को नए जगहों पर बसाने से उनकी गरीबी बढ़ सकती है, परिवार टूट सकते हैं और एक बाड़े के भीतर पशुओं द्वारा बहुत ज्यादा चराई करने से मिट्टी में क्षरण को बढ़ावा मिल सकता है।

नेपाल को चीन विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रशिक्षण दे रहा है चीन

(पीटीआई, 10 नवंबर)

नेपाल में चीन विरोधी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने की कोशिशों के तहत चीन नेपाली पुलिसकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहा है।

नेपाली गृह मंत्रालय के अनुसार रसुआ, सिंधूपल चौक, दोलखा, मस्तांग और सोलुखुंबु जिले के नेपाल पुलिसकर्मी और सशस्त्र पुलिस बल के जवान दो सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए बीजिंग गए हुए हैं। कांतिपुर ऑनलाइन में 9 नवंबर को कहा गया कि इस प्रशिक्षण में कास्की और डोल्पा के जिला मुख्य अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से नेपाल में चीन विरोधी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के प्रयास को बल मिलेगा, खासकर नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों की मौजूदगी के कारण। चीन ने नेपाल में रह रहे शरणार्थियों द्वारा बीजिंग विरोधी प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए नेपाल सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। हाल ही में चीन यात्रा के दौरान नेपाली राष्ट्रपति राम बरन यादव ने चीनी प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ को आश्वस्त किया था कि वे नेपाल में चीन के हित को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे।

चीन पर्यटन के सहारे तिब्बत पर कर रहा है कब्जा

(दि इंडीपेंडेंट, 3 नवंबर)

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र ल्हासा में 1950 में चीनी सेना के अतिक्रमण और वहां हान चीनी संस्कृति को थोपने के बाद से सदियों पुराने इस अलग–थलग धार्मिक क्षेत्र में काफी कुछ बदल चुका है। यहां रोजाना की हवाई सेवा और अत्याधुनिक रेल सेवा जैसे क्विंघई–तिब्बत रेल सेवा शुरू होने के बाद पर्यटकों का रेला देखा जा सकता हैं। जबकि पहले यहां न तो चीनी और न ही किसी अन्य देश के लोग आने का साहस करते थे। यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में 2010 के पहले नौ महीनों में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा बढ़कर 58 लाख तक पहुंच गया है। चीन के नव धनाढ्य लोगों के लिए यहां टिकने के लिए आधुनिक और महंगी सुविधाएं हैं। ल्हासा में किसी नए स्थान पर एक रात ठहरने के लिए आपको 200 पाउंड खर्च करने पड़ सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में यहां शांग्री–ला और इंटरकांटिनेंटल होटल समूह भी अपने महंगे श्रेणी के होटल शुरू करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में हुआ यह बदलाव हालांकि सहजता से नहीं हुआ। मार्च 2008 में यहां हान चीनी समुदाय के विरोध में हुए एक हिंसक विद्रोह में चीन सरकार के आंकड़े के मुताबिक 22 लोगों की मौत हो गई थी। तिब्बत के मानवाधिकारवादी समूहों का हालांकि कहना था कि वास्तविक संख्या इससे बहुत अधिक है। चीन सरकार के अधिकारियों ने इस विद्रोह के लिए दलाई लामा के समर्थक अलगाववादियों पर आरोप लगाया था।

अभी यहां धार्मिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ल्हासा की हर गलियों में भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। ल्हासा हालांकि दुनिया के सबसे अलग–थलग शहरों में आता है, लेकिन चीन दुनिया भर में इसका प्रचार एक पर्यटन केंद्र के रूप में कर रहा है। तिब्बत के

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से नेपाल में चीन विरोधी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के प्रयास को बल मिलेगा, खासकर नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों की मौजूदगी के कारण। चीन ने नेपाल में रह रहे शरणार्थियों द्वारा बीजिंग विरोधी प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए नेपाल सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।

इन तीनों ने चीन सरकार के खिलाफ धारगे गोंपा में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बड़ी संख्या में यहां हान चीनी लोगों के आने से तिब्बत की विशिष्ट संस्कृति को नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही तिब्बती लोगों को नई नौकरियों और आर्थिक गतिविधियों में समुचित हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। तिब्बत की स्वायत्तता की मांग करने वाले विदेशी समूहों का कहना है कि तिब्बत को इस तरह से खोलने से बड़ी संख्या में हान चीनी लोगों का यहां आगमन हो सकता है और वे तिब्बतियों को उनके गृह क्षेत्र में ही हाशिए पर धकेल सकते हैं।

दो तिब्बती कारोबारियों को 15 साल जेल की सजा

जिन लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया वे खासकर इस बात से दुखी थे कि चीन सरकार की कार्रवाई में सभी तिब्बतियों को निशाना बनाया जा रहा है चाहे किसी ने इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिस्सा लिया हो या नहीं।

(टिबेटन रीव्यू डॉट नेट, 20 नवंबर)

तिब्बत के ल्होका प्रशासनिक क्षेत्र के माध्यमिक जन न्यायालय ने दो तिब्बती कारोबारियों को 15 साल जेल की सजा सुनाई है। धर्मशाला के तिब्बती मानवाधिकार केंद्र ने 18 नवंबर को यह जानकारी दी है। इन दोनों व्यापारियों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अगस्त 2009 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यह भनक किसी को नहीं लग पाई कि कब इसके लिए मुकदमा चला और उनका अपराध ा साबित भी हुआ कि नहीं। जेल की इस सजा का खुलासा होने तक किसी को भी यह भी नहीं पता चल पाया था कि 45 साल के सोनम भागद्रो और 30 साल के टाशी तोपग्याल को कहां रखा गया है।

दो तिब्बती भिक्षुओं को साढ़े नौ साल कारावास की सजा

(टिबेटन रीव्यू डॉट नेट, 24 नवंबर)

तिब्बत के जोमदा काउंटी अदालत द्वारा दो भिक्षुओं को 9 साल 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है। इन भिक्षुओं पर आरोप है कि इन्होंने 10 मार्च को तिब्बत की राष्ट्रीय जनक्रांति की 51वीं वर्षगांठ पर सरकारी वाहनों को आग लगाया है। अदालत ने 25 अक्टूबर को 26 साल के कर्मा पालसांग और 22 साल के मिफाम गेलेक को यह सजा सुनाई। यह दोनों भिक्षु छामदो प्रशासनिक क्षेत्र के स्थानीय जिगार मठ से जुड़े हैं। मार्च 2010 की घटनाओं के बाद चीन सरकार द्वारा बड़े पैमाने और क्रूरता से सुरक्षा बलों के इस्तेमाल और अनुचित दबाव के विरोध में पहली बार सिचुआन प्रांत के कार्जे काउंटी में खेती बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद बड़े पैमाने पर तिब्बतियों का यह विरोध प्रदर्शन छामदो प्रशासनिक क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर भी फैल गया। जिन लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया वे खासकर इस बात से दुखी थे कि चीन सरकार की कार्रवाई में सभी तिब्बतियों को निशाना बनाया जा रहा है चाहे किसी ने इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिस्सा लिया हो या नहीं। लोगों ने यह संदेश दिया कि ऐसे शासन के तले रहने की बजाय भूख हड़ताल कर अपनी जान देना पसंद करेंगे।

भारी यातना के बाद तिब्बती नन को रिहा किया गया

(टिबेटन रीव्यू डॉट नेट, 27 नवंबर)

सिचुआन प्रांत के कांडजे काउंटी के अधिकारियों ने 19 नवंबर को एक भिक्षुणी को रिहा किया है। दो साल जेल की सजा के दौरान जेल अधिकारियों की पिटाई की वजह से उनका स्वास्थ्य बेहद खराब हो गया था। ओस्लो के वायस ऑफ टिबेट रेडियो पर 25 नवंबर को सेरा मठ के एक भिक्षु पेमा सेवांग ने कांडजे के अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि टागा (टाशी यांगजोम) नाम की इन भिक्षुणी के दाहिने हाथ में दो जगह फ्रैक्चर हो गया था, उन्हें दाहिने कान से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और उन्हें टीबी एवं श्वसन संबंधी कई समस्याएं हो गई थीं। फिलहाल प्रांत की राजधानी चेंगदू के एक अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। टागा को 20 मई, 2008 को दो अन्य भिक्षुणियों आछो और सोछो के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन तीनों ने चीन सरकार के खिलाफ धारगे गोंपा में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। तीनों भिक्षुणियां टेहोर न्याग्ये ननरी से जुड़ी थीं। आछो रिदा गांव की, सो छोक्यी लामना गांव की और

टागा नोएकाब गांव की रहने वाली हैं। इन भिक्षुणियों के साथ ही कार्डजे काउंटी में द्रुकार ननरी से 12 भिक्षुणियों, पांग–री ननरी से 55 भिक्षुणियों और गांदेन छोलिंग ननरी से कई अन्य भिक्षुणियों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार तिब्बती लेखक के कैद के स्थान का पता लगा

(रेडियो फ्री एशिया, 20 नवंबर)

तिब्बती लेखक टाशी राबतेन को 6 अप्रैल को लांजू शहर के नॉर्थवेस्ट माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जाकर यह पता चल पाया है कि वे कहां हैं। उन्हें सिचुआन प्रांत के गबा प्रशासनिक क्षेत्र के बरखाम काउंटी के एक कारावास में रखा गया है। टाशी को एक अन्य व्यक्ति ड्रुकलो के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ड्रुकलो को मई में रिहा कर दिया गया। यह भी किसी को नहीं बताया गया है कि उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विश्वविद्यालय में 16 पुलिस अधिकारियों के एक दल ने छात्रावास पर धावा बोलकर छात्रों के कमरों की तलाशी ली और उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और किताबें जब्त कर लीं। इसके बाद टाशी को गिरफ्तार कर लिया गया। टाशी राबतेन ने प्रतिबंधित साहित्यिक पत्रिका शार डुंगरी (पूर्वी बर्फीला पहाड़) का संपादन किया था। इस पत्रिका में तिब्बत में 2008 में हुए विरोध प्रदर्शनों की खबरें प्रकाशित की गई थीं। इसके अलावा टाशी एक पुस्तक 'रिटेन इन ब्लड' (रक्त से लिखा) के सहलेखक भी हैं। सिचुआन प्रांत के जोएगे काउंटी के निवासी टाशी का इसी साल ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था।

आमदो गाबा के तीन तिब्बती लेखकों पर अलगाववाद का मुकदमा

(रेडियो फ्री एशिया, 5 नवंबर)

एक स्थानीय तिब्बती पत्रिका शार डुंगरी में साल 2008 में तिब्बत में हुए प्रदर्शनों के बारे में लिखने की वजह से जून एवं जुलाई माह में तीन युवा तिब्बती लेखकों को गिरफ्तार किया गया था। अब सिचुआन प्रांत के गबा माध्यमिक न्यायालय में 28 अक्टूबर को उन पर अलगाववाद फैलाने का मुकदमा किया गया है। 32 साल के जांगत्से दोनखो (पुकारने का नाम नेन), 34 साल के बुद्ध और कालसांग जिनपा (पुकारने का नाम गार्मी) को 'देश को तोड़ने की गतिविधियों को भड़काने' के लिए मुकदमा किया गया है। अदालत ने अभी इस पर अपना निर्णय नहीं दिया है। इन तीनों लेखकों पर एक साथ मुकदमा शुरू हुआ और यह करीब आधा दिन चला। तीनों ने अपने ऊपर लगाए आरोपों से इनकार किया है। अदालत से बाहर आने के कुछ मिनट बाद बुद्ध के परिवार के लोग उससे मिलने आए। बेड़ियों में जकड़े होने के कारण वह अपने दो साल के बच्चे को गोंद में नहीं ले पाए, उन्होंने उसका दो बार चुंबन लिया और अपनी पत्नी से यह भरोसा लिया कि उनका बेटा तिब्बती भाषा जरूर सीखेगा। इसके बाद सुरक्षा बल के लोग उन्हें लेकर आगे बढ़ गए। बुद्ध ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया है कि उन्होंने कोई अपराध किया है। उन्होंने कहा, "उन्हें और उनके अन्य साथियों को जिस तरह के लेख लिखने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है उस तरह के लेख कई हान चीनी पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं। लेकिन हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए आप हमें कैद, मुकदमे और जेल की सजा दे रहे हैं।"

विश्वविद्यालय में 16 पुलिस अधिकारियों के एक दल ने छात्रावास पर धावा बोलकर छात्रों के कमरों की तलाशी ली और उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और किताबें जब्त कर लीं। इसके बाद टाशी को गिरफ्तार कर लिया गया।

दो साल से गिरफ्तारी से बच रहे तिब्बती प्रदर्शनकारी ने भारत आकर पायी आज़ादी

(रेडियो फ्री एशिया, 29 नवंबर)

साल 2008 में चीनी शासन के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए चीनी पुलिस द्वारा तलाश किए जा रहे एक तिब्बती व्यक्ति गिरफ्तारी से बचते हुए आखिरकार सीमा पार कर सुरक्षित भारत पहुंच गया। तिब्बत के सिचुआन प्रांत के कार्डजे क्षेत्र में स्थित शुसोर के मूल निवासी नामसा वांगडेन नवंबर के तीसरे सप्ताह में अपने पत्नी एवं बच्चों के साथ धर्मशाला पहुंचे। वांगडेन ने करीब दो साल पहले कार्डजे में हुए उस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यद्यपि तिब्बत में तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं और तिब्बत की काफी हद तक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को नष्ट किया जा चुका है (ज्यादातर 1967 से 1977 के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गलत नाम वाले सांस्कृतिक क्रांति के दौरान हुआ), फिर भी तिब्बती जनता के लिए तिब्बत एक पवित्र भूमि बना हुआ है।

था जिसमें शामिल बहुत से तिब्बती नागरिक ज्यादा आज़ादी और परमपावन दलाई लामा को वापस बुलाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पहले चीनी पुलिस ने लोहे के सलाखों का प्रयोग किया लेकिन बाद में लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद करीब चार महीने तक वांगदेन न्यारोंग के जंगलों में छुपे रहे और इस दौरान उन्हें कई दिनों तक कुछ खाने को नसीब नहीं हुआ। इसके बाद वह उस क्षेत्र में रह रहे कुछ तिब्बती खानाबदोश लोगों के समूह में शामिल हो गए। इसके बाद वह अपने एक दोस्त की मदद से तिब्बत की राजधानी ल्हासा पहुंच गए जहां दोस्त के परिवार वाले उनसे मिले। इसके बाद वांगदेन ने अपने परिवार के साथ सीमा पार कर नेपाल जाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि वह करीब तीन साल से सुरक्षा बलों की पहुंच से भागते फिर रहे हैं। वांगदेन ने बताया कि जिस क्षेत्र से होकर वे आए हैं वहां जबर्दस्त सुरक्षा इंतजाम थे। उन्होंने बताया कि सीमा पर चीनी सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है और वे बड़ी मुश्किल से गिरफ्तारी से बच पाए। गौरतलब है कि मार्च 2008 में ल्हासा में जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे जो पश्चिमी चीन के तिब्बती जनसंख्या वाले क्षेत्रों तक फैल गए थे। इसकी वजह से अगस्त 2008 में होने वाले बीजिंग ओलंपिक से पहले चीन को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। भारत स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार का अनुमान है कि इस समूचे क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई से कम से कम 220 तिब्बती मारे गए और 7,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

तिब्बती भाषा के समर्थन में यूरोपीय संसद में प्रस्ताव पारित हुआ

(टिबेट डॉट नेट, 25 नवंबर)

तिब्बत में पढ़ाई का मुख्य माध्यम चीनी भाषा को बनाने की चीन सरकार की योजना की आलोचना करते हुए यूरोपीय संसद ने 23 नवंबर को एक प्रस्ताव कर ऐसी भाषा नीति का समर्थन किया जिसमें सभी विषय तिब्बती भाषा में पढ़ाई जा सकें। यूरोपीय संसद ने एक बयान जारी कर कहा, "तिब्बत पर जारी एक प्रस्ताव में यूरोपीय संसद के सदस्यों ने चीनी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वह ऐसी सही द्विभाषा नीति का समर्थन करें जिसमें सभी विषय तिब्बती भाषा में ही पढ़ाई जाएं। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि करीब 60 लाख तिब्बतियों की सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बुनियादी आज़ादी पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और चीनी अधिकारी तिब्बत में पढ़ाई का माध्यम चीनी भाषा को बनाने की तैयारी हो रही है।

दलाई लामा को मदर टरेसा शांति एवं सामाजिक न्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया

(टिबेट डॉट नेट, 19 नवंबर)

परमपावन दलाई लामा को हार्मोनी फाउंडेशन ने शांति एवं सामाजिक न्याय के लिए मदर टरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया है। हार्मोनी फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. अब्राहम मथाई ने कहा कि यह सम्मान परमपावन को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वह 'एक जीवित किवदंती हैं, दुनिया भर में विवेक के प्रतीक हैं, एक ऐसी आवाज हैं जो टकराते मूल्यों के कोलाहल में भी सुनी जाती है और शांति एवं सामाजिक न्याय की वैश्विक आवाज हैं।'

इस पुरस्कार को स्वीकार करने के अपने भाषण में परमपावन ने कोलकाता में मदर टरेसा के केंद्र में अपने पहले दौरे को याद किया। उन्होंने बताया कि वह मदर टरेसा की जीवटता से बहुत प्रभावित हुए और यह बात मदर के न रहने के बावजूद भी उनकी यादों में जिंदा है। परम पावन ने कहा, "यह बात बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके न रहने के बावजूद उनके शिष्य गरीबों और वंचितों की सेवा की उनकी विरासत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।"

आडवाणी ने कहा, तिब्बत में हो रहे हैं अत्याचार

(फायूल, 8 नवंबर)

सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर तिब्बत में 'अत्याचार' के लिए चीन पर हमला बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने रविवार को यह उम्मीद जताई कि दलाई लामा सहित निर्वासन में रह रहे सभी तिब्बती नागरिक जल्दी ही अपने घर जाने में कामयाब हो जाएंगे।

भारतीय संसद में नेता विपक्ष रह चुके श्री आडवाणी ने यह भी उम्मीद जताई कि निर्वासित तिब्बती नेता और निर्वासन में रह रहा तिब्बती समुदाय अपने मातृभूमि एक 'सम्मानजनक' और 'गौरवपूर्ण' तरीके से वापस लौट सकेगा और तिब्बत के भाग्य का निर्माण करेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यद्यपि तिब्बत में तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं और तिब्बत की काफी हद तक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को नष्ट किया जा चुका है (ज्यादातर 1967 से 1977 के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गलत नाम वाले सांस्कृतिक क्रांति के दौरान हुआ), फिर भी तिब्बती जनता के लिए तिब्बत एक पवित्र भूमि बना हुआ है। आडवाणी ने अपने ब्लॉग पर नवीनतम पोस्ट में भी लिखा है, "मैं यह उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब निर्वासन को मजबूर कर दिए गए परमपावन दलाई लामा और अन्य तिब्बती नागरिक अपनी मातृभूमि और पवित्र भूमि में सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण तरीके से वापस लौट सकेंगे और इसके बाद तिब्बत के भाग्य का निर्धारण करने में सक्षम होंगे।"

आडवाणी ने दिल्ली के नजदीक सूरजकुंड में तिब्बत समर्थक समूहों के छठे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में परमपावन दलाई लामा भी शामिल हुए। आडवाणी ने कहा कि चीन सरकार को एक गंभीर और वास्तविक संवाद करने के इरादे से दलाई लामा से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा, "तिब्बत मसले को हल करने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं के इस सजीव मूर्तरूप से ज्यादा तार्किक और शांतिप्रिय संभाषी नहीं मिल सकता।"

अंतरराष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूहों के सम्मेलन में आडवाणी ने नवंबर, 2006 में चीनी राष्ट्रपति हू चिनताओ के भारत आगमन पर उनसे अपनी मुलाकात के क्षणों को याद किया। उन्होंने बताया, "इस मुलाकात के दौरान मैंने चीनी नेताओं से अनुरोध किया कि वे चीन में ऐसा माहौल तैयार करें जिससे बीजिंग ओलंपिक से पहले परमपावन तिब्बत का दौरा कर सकें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि चीन ने यह मौका गवां दिया।" इस बात को देखते हुए कि इस सम्मेलन में 56 देशों के 260 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, आडवाणी ने कहा कि पहली बार चीन की मुख्य भूमि से ऐसे प्रतिनिधि आए हैं जिन्होंने तिब्बती आंदोलन का खुलकर मजबूती से समर्थन किया है। इस सम्मेलन के माध्यम से आडवाणी की इस साल में दूसरी बार परमपावन से मुलाकात हुई। दोनों नेता इसके पहले अप्रैल माह में हरिद्वार के कुंभ मेले में मिले थे और तब दोनों ने साथ मिलकर उत्तराखंड सरकार की हिंदू एनसाइक्लोपीडिया और स्पर्श गंगा परियोजनाओं की शुरुआत की थी। स्पर्श गंगा परियोजना गंगा की सफाई के लिए है। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा, "इस साल दूसरी बार मुझे परमपावन दलाई लामा के साथ मंच साझा करने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ।"

उन्होंने कहा, "तिब्बत मसले को हल करने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं के इस सजीव मूर्तरूप से ज्यादा तार्किक और शांतिप्रिय संभाषी नहीं मिल सकता।"

भारत में दलाई लामा का कद बढ़ा

(फाइनेंशियल टाइम्स, 29 नवंबर)

निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामा को पिछले हफ्ते दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा मानद डिग्री देने से पहले वहां के उपकुलपति श्री नजीब जंग ने भारत के विदेश मंत्रालय से इजाजत मांगी, इस आशंका की वजह से कि भारत के हिमालय पार के नाजुक कूटनीतिक संबंधों में कोई गड़बड़ी न हो जाए। जब इस बात की इजाजत मिल गई तो श्री जंग ने विश्वविद्यालय के 3,500 छात्रों को भी इसी अवसर पर डिग्री देने का निर्णय लिया ताकि 'उन्हें परमपावन की उपस्थिति और उनके द्वारा साझा किए जाने वाले मूल्यों का लाभ मिले। लेकिन चीन का व्यवहार बेहद खराब रहा। चीन सरकार लगातार इस बात का प्रयास करती रही है कि तिब्बती राष्ट्रीयता के शक्तिशाली प्रतीक

इस बात को देखते हुए कि इस सम्मेलन में 56 देशों के 260 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया,

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आं

1. सूरजकुंड में 5 नवंबर, 2010 को तिब्बत समर्थक समूहों के तीन दिवसीय अंत श्री लालकष्ण आडवाणी
2. यांगून में 14 नवंबर, 2010 को आंग सान सू की अपनी पार्टी नेशनल लीग प हजारों समर्थकों से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो ज को प्यार करती हूं"। फोटोः रायटर्स
3. तिब्बत में साल 2008 में हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर आधारित एक पुस्तक लालकृष्ण आडवाणी, परमपावन दलाई लामा और कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज
4. नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के 11वें विश्व सम्मेलन के तीसरे दिन 14 न
5. तिब्बत के प्रधानमंत्री के लिए होने वाले चुनावों के प्रारंभिक चरण में हार्वर्ड ल लोबसांग सेंगे भारी मतों से आगे चल रहे हैं
6. धर्मशाला के स्टाफ मेस ऑडिटोरियम में 10 नवंबर को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन फंग, न्यूयॉर्क के तिब्बत कार्यालय में चीनी लायजन अधिकारी श्री कुंगा टाशी,
7. नई दिल्ली में 23 नवंबर, 2010 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के उपकुलपति नजीब जंग (बाएं) परमपावन दलाई लामा
8. इस फाइल फोटो में परमपावन दलाई लामा 1960 में एक तिब्बती शरणार्थी शै
9. ताइपेई में 11–12 नवंबर, 2010 को 'चीन में लोकतंत्र की संभावनाएं एवं तल
10. न्याय के लिए आह्वानः देरगे पालयुल काउंटी की निवासी सोनम सेरिंग को

(9)

(8)

(3)

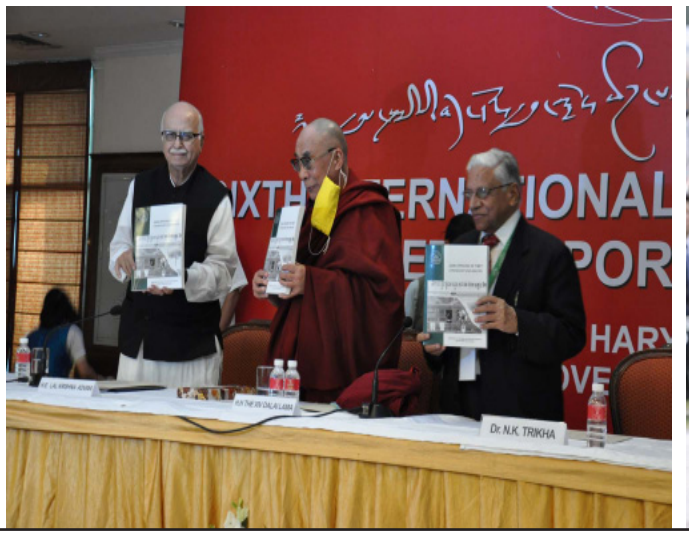

(4)

ंख से तिब्बत

रराष्ट्रीय सम्मेलन का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते परमपावन दलाई लामा और

फॉर डेमाक्रेसी के मुख्यालय के बाहर समर्थकों को संबोधित करते हुए। उन्होंने अपने
ाएं और हार नहीं मानें। इस अवसर पर लगे बैनरों पर लिखा हुआ था, "मैं भी जनता

क का लोकार्पण करते हुए (बाएं से) भाजपा नेता एवं भारत के पूर्व उपप्रधान मंत्री श्री
न के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. नंदकिशोर त्रिखा
वंबर, 2010 को हिरोशिमा मेमोरियल पार्क में पहुंचते नोबेल पुरस्कार विजेता
ॉ स्कूल में पूर्वी एशियाई कानून अध्ययन कार्यक्रम के सीनियर रिसर्च फेलो डॉ.

न के अधिकारियों से बात करते (दाएं से) श्री जियांग जियो जी, सुश्री ग्लोरिया वाई
श्री झू जू युआन और श्री जिया मिंग
के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल
को मानद डी.लिट. डिग्री प्रदान करते हुए
क्षणिक संस्थान की कक्षा का निरीक्षण करते दिख रहे हैं
ाश' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया
दो साल के लिए विलंबित मौत की सजा सुनाई गई है

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

(7)

(6)

दलाई लामा को अलग–थलग कर दिया जाए और वह दुनिया भर के नेताओं पर इस बात के लिए दबाव बनाता रहा है कि वे परमपावन से न मिलें। लेकिन चीनी प्रधानमंत्री के भारत दौरे से कुछ दिनों पहले ही भारतीय राजधानी में दलाई लामा का कद काफी बढ़ गया है। एक तरफ भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने सीमा विवाद को सुलझाने में लगे रहे तो दूसरी तरफ परमपावन दिल्ली में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। 76 साल के तिब्बती नेता अपने उत्तराधिकारी को लेकर भी काफी भरोसमंद दिखे। उन्होंने कहा कि चीन इस मसले को इसलिए उठा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मौजूदा नेता के साथ ही तिब्बती राष्ट्रीयता का मसला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत दलाई लामा उत्तर भारत के धर्मशाला शहर में स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार की भूमिका और बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हमारा मानना है कि तिब्बत के भविष्य की चाबी बौद्ध आध्यात्मिक अवतारों की 400 साल पुरानी संस्था के मुकाबले लोकतांत्रिक नेतृत्व के हाथों में होगी। उन्होंने कहा है कि उनका अवतार संभवतः चीनी नियंत्रण वाले तिब्बत से बाहर आंदोलन की पृष्ठभूमि में होगा। उन्होंने कहा, "यदि तिब्बत से बाहर रहने पर मेरी मौत होती है तो तार्किक बात है कि मेरे नए अवतार का मुख्य उद्देश्य मेरे पिछले जीवन में शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए अवतार ऐसा होना चाहिए जो मेरे संघर्ष को लगातार आगे बढ़ा सके। तार्किक बात है कि मेरा अवतार तिब्बत के बाहर ही जन्म लेगा।" देश के प्रख्यात टीवी पत्रकार करन थापर को दिए इंटरव्यू में परमपावन ने कहा कि अगले छह माह में वह अपनी सार्वजनिक जवाबदेही कम करते हुए सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दलाई लामा के दिल्ली में व्यस्त कार्यक्रमों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह इतनी जल्दी पीछे नहीं हटने वाले।

परमपावन ने कहा, "मैंने यह सुना है कि तिब्बत के कई मठों को सिर्फ संग्रहालय जैसा बना दिया गया है और भिक्षु सिर्फ उनकी देखभाल करने वाले जैसे रह गए हैं। पिछले 20 साल से मैं यह सुन रहा हूं कि जाने या अनजाने तिब्बत में एक तरह का सांस्कृतिक संहार चल रहा है।

तिब्बत में सांस्कृतिक संहार कर रहा है चीनः दलाई लामा

(फायूल, 21 नवंबर)

पिछले 20 साल से जाने या अनजाने तिब्बत में एक तरह का सांस्कृतिक संहार चल रहा है। सीएनएन–आईबीएन न्यूज चैनल के डेविल्स एडवोकेट कार्यक्रम में पत्रकार करन थापर को दिए इंटरव्यू में परमपावन दलाई लामा ने यह बात कही। परमपावन ने कहा, "मैंने यह सुना है कि तिब्बत के कई मठों को सिर्फ संग्रहालय जैसा बना दिया गया है और भिक्षु सिर्फ उनकी देखभाल करने वाले जैसे रह गए हैं। पिछले 20 साल से मैं यह सुन रहा हूं कि जाने या अनजाने तिब्बत में एक तरह का सांस्कृतिक संहार चल रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए और शोध कार्य करना होगा। तिब्बत के स्कूलों में पढ़ाई के माध्यम के रूप में चीनी भाषा को बढ़ाने के सवाल पर दलाई लामा ने कहा कि कुछ तिब्बतियों ने उन्हें बताया है कि तिब्बत में एक तरह की 'अर्द्ध सांस्कृतिक क्रांति' चल रही है और जल्दी ही तिब्बती भाषा का खात्मा हो सकता है। अपनी भाषा और संस्कृति पर आए खतरे से लड़ने के लिए तिब्बती क्या कर रहे हैं, इस सवाल पर दलाई लामा ने कहा, "हम इसके लिए चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर ही वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं।

तिब्बती स्कूल की 50वीं वर्षगांठ पर दलाई लामा ने भारत को धन्यवाद दिया

(फायूल, 16 नवंबर)

निर्वासित तिब्बतियों के पहले स्कूल मसूरी के 'द सेंट्रल स्कूल फॉर टिबेटंस' की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर परमपावन दलाई लामा ने भारत सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने बीते दिनों को याद करते हुए बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तिब्बती बच्चों को शिक्षित करने में गहरी रुचि दिखाई थी और निर्वासन के शुरुआती दिनों में ही तिब्बती बच्चों के लिए अलग स्कूल खोले। इस अवसर पर दलाई लामा ने कहा, "अप्रैल 1959 में हमारे भारत आगमन के बाद प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मुझे आश्वस्त किया कि तिब्बत आंदोलन को आगे बढ़ाने का असल तरीका यह है कि तिब्बती बच्चों को पर्याप्त शिक्षा दी जाए। उन्होंने अपने इस परामर्श पर अमल करते हुए तिब्बतियों के

लिए अलग स्कूल खोलने में व्यक्तिगत रुचि दिखाई। इसके लिए भारत सरकार से सीधा सहयोग एवं समर्थन मिला।"

निर्वासित तिब्बती सरकार के शिक्षा मंत्री थुबतेन लुंगरिग, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री एस.सी. खुंतिया, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा सचिव पूज्यनीय कर्मा गेलेक और सीटीएसए के निदेशक श्री आलोक वर्मा ने इस समरोह में हिस्सा लिया। परमपावन ने कहा कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करना बहुत दूर तक उदारता के प्रसार का कार्य है। उन्होंने कहा, "जब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है तो एक व्यक्ति के रूप में न केवल उन्हें अपने को सुधारने का मौका मिलता है बल्कि वे पूरे समाज के विकास में योगदान कर सकते हैं।"

परमपावन के आशीर्वाद से इस स्कूल की स्थापना 3 मार्च 1960 को 'तिब्बती शरणार्थी शैक्षणिक संस्थान' के रूप में सिर्फ 6 शिक्षकों और 50 बच्चों के साथ हुई थी। मसूरी का तिब्बती स्कूल भारत में स्थापित होने वाला पहला आवासीय तिब्बती स्कूल बना जिसका संचालन निर्वासित तिब्बती सरकार के सहयोग से भारत सरकार कर रही है।

दलाई लामा ने खुद को भारत का बेटा बताया

(वाल स्ट्रीट जर्नल, 19 नवंबर)

''मैं भारत का बेटा हूं''। यह जवाब दलाई लामा का है। उन्होंने नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में यह कहा। भारत न सिर्फ तिब्बत से आने के बाद उनका आश्रय स्थल रहा है, बल्कि उनके ही शब्दों में ''यह शरीर भारतीय दाल और भात खाकर बड़ा हुआ है। इसलिए मैं अपने को भारत का बेटा कहता हूं।'' उन्होंने खुद को भारत का दूत भी कहा। क्योंकि वे प्राचीन भारतीय विचारों खासकर अहिंसा और करुणा के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि भारत उनकी राय में एकमात्र देश हैं, जहां सभी धर्मों के लोग सम्मान के साथ रह सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हालांकि, पुराने रिवाज जैसे जातिवाद और दहेज प्रथाओं को बदलने की जरूरत है। नक्सलवाद की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि भारत में जहां एक ओर बड़े शहर हैं, वहीं ऐसी भी आबादी है, जिन्हें बिजली और शिक्षा की सुविधा तक नहीं मिल पाई है। इसके कारण वे नक्सलवादियों के प्रभाव में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक–से–अधिक पुलिस भेजने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए सेवा उपलब्ध करानी होगी। यह पूछने पर कि वे अपने उत्तराधिकारी चुनने की योजना पर क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ''मेरे लिए यह कोई गंभीर सवाल नहीं है''। उसके बाद उन्होंने कहा कि ''ऐसा लगता है कि चीन सरकार इस मामले में सचमुच गंभीर है।'' उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी परंपरा के बाद भी वे ऐसा नहीं सोचते कि किसी भी कीमत पर उत्तराधिकार का चुनाव किया ही जाना चाहिए। परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है और यह तिब्बत के लोगों पर निर्भर करता है कि वे इस पद को जारी रखना चाहते हैं कि नहीं।

उन्होंने कहा कि ''जहां तक दलाई लामा संस्था की बात है, चीनी मानस और साम्यवादी मानस इस विषय को लेकर मुझसे अधिक फिक्रमंद है।''

भारत न सिर्फ तिब्बत से आने के बाद उनका आश्रय स्थल रहा है, बल्कि उनके ही शब्दों में ''यह शरीर भारतीय दाल और भात खाकर बड़ा हुआ है। इसलिए मैं अपने को भारत का बेटा कहता हूं।''

चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में बांध बनाए जाने पर भारत चिंतित

(टिबेटन रीव्यू डॉट नेट, 17 नवंबर)

चीन ने खुद कहा है कि 12 नवंबर से उसने ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में एक बांध का निर्माण शुरू किया है जो तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के ल्होका प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित जांगमू में बनने जा रहे विशाल जलविद्युत परियोजना के मुख्य हिस्से की इमारत बनने की दिशा में पहला कदम है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है।

करीब 1.2 अरब डॉलर की लागत से बनने वाले बिजली प्लांट में 85 मेगावॉट उत्पादन की छह इकाइयां होंगी और ल्हासा से करीब 325 किलोमीटर दूर स्थित इस केंद्र की सालाना औसत

यह परियोजना टीएआर में पहला बड़ा जल विद्युत केंद्र होगा और इसकी पहली यूनिट साल 2014 से चालू हो जाएगी।

वांग ने कहा ,"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका के समर्थन के बाद भारत में ऐसे दुस्साहसी समूह बढ़ रहे हैं।"

उत्पादन क्षमता करीब 2.5 अरब किलोवॉट घंटा होगी। यह परियोजना टीएआर में पहला बड़ा जल विद्युत केंद्र होगा और इसकी पहली यूनिट साल 2014 से चालू हो जाएगी। पीपुल्स डेली ऑनलाइन में छपी खबर के मुताबिक इस जलविद्युत केंद्र का मुख्य कार्य तो बिजली उत्पादन ही होगा, लेकिन इसको बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

असम ट्रिब्यून अखबार के ऑनलाइन संस्करण में 11 नवंबर को छपी खबर के अनुसार भारत के जल संसाधन राज्य मंत्री विनसेट एच पाला ने संसद में जानकारी दी है कि अप्रैल, 2010 में चीन ने भारत को बताया था कि जांगमू एक छोटी परियोजना होगी और इसका मुख्य कार्य बिजली उत्पादन होगा, न कि जल आपूर्ति पर नियंत्रण। लेकिन चीन का यह भरोसा पूरी तरह झूठा साबित हुआ है।

चीन ने कहा, अरुणाचल में भारत द्वारा सैनिकों की संख्या बढ़ाना एक 'गलत कदम'

भारत विशेषज्ञ वांग देहुआ ने कहा, "चीन के साथ 1962 में युद्ध के बाद भारतीय सेना ने इस इलाके में कुल 10 पर्वतीय डिवीजन स्थापित किए हैं।

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 23 नवंबर)

चीन द्वारा तिब्बती सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती को देखते हुए भारत भी उत्तर–पूर्व में नए सैनिक दस्तों की तैनाती कर रहा है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा के पास दो नए इन्फैंटी (पैदल सेना) डिवीजन तैनात किए हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र मानने का दावा करता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों इन्फैंटी पर्वतीय डिवीजन में 1,260 अधिकारी और 35,011 सैनिक हैं और इसे साल 2011 तक 'खास साजोसामान के साथ पूरी तरह संचालित' कर दिया जाएगा। इसी तरह अरुणाचल स्काउट्स की पहली बटालियन भी मई 2011 तक खड़ी हो जाएगी और संचालित होने लगेगी। एक अधिकारी ने बताया, "फिलहाल सरकार ने अरुणाचल स्काउट के एक बटालियन को मंजूरी दी है। सिक्किम स्काउट भी खड़ा करने की योजना है।"

साल 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में लद्दाख स्काउट की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उसे पूर्ण इन्फैंटी रेजिमेंट में बदल दिया गया था। अरुणाचल स्काउट भी इसी तरह के 'भूमिपुत्र' अवधारणा पर आधारित है। दूसरी तरफ चीनी विशेषज्ञों ने भारतीय तैयारी को यहां की सरकार का 'गलत कदम' बताया है। चीन के सरकारी स्वामित्व वाले ग्लोबल टाइम्स से शंघाई अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में भारत विशेषज्ञ वांग देहुआ ने कहा, "चीन के साथ 1962 में युद्ध के बाद भारतीय सेना ने इस इलाके में कुल 10 पर्वतीय डिवीजन स्थापित किए हैं। इस प्रकार के कदम सीमा विवाद पर आगामी भारत–चीन वार्ता में गतिरोध पैदा करने की ही कोशिश है। वांग ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका के समर्थन के बाद भारत में ऐसे दुस्साहसी समूह बढ़ रहे हैं।"

भारत ने जम्मू–कश्मीर की तुलना तिब्बत से की?

(इंडियन एक्सप्रेस, 15 नवंबर)

अगले महीने चीनी प्रधानमंत्री वन च्यापाओ की यात्रा से करीब एक माह पहले भारत ने यह साफ किया है कि उसे उम्मीद है कि चीन कश्मीर पर कोई सीधा नजरिया पेश करेगा जैसा कि भारत ने तिब्बत और ताइवान में चीन की संवदेनशीलता का ध्यान रखा है। 14 नवंबर को रूस–भारत–चीन के त्रिपक्षीय बैठक से पहले चीनी विदेश मंत्री यांग छिजी से करीब 70 मिनट तक चलने वाली द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने यह संदेश चीन तक पहुंचाया है।

हालांकि यांग की इस मामले में प्रतिक्रिया लगातार गोलमोल बनी रही और इस दौरान यह मसला भी नहीं उठाया गया कि नई दिल्ली ने उच्च स्तरीय सैन्य आदान–प्रदान पर विराम लगा दिया है क्योंकि बीजिंग ने कहा था कि उसने उत्तरी क्षेत्र के थल सेना कमांडर को नत्थी वीजा देने का निर्णय लिया क्योंकि वह एक 'विवादास्पद क्षेत्र' के प्रभारी हैं।

इस वार्ता का विवरण देते हुए विदेश सचिव

निरुपमा राव ने कहा कि भारत जिस तरह ताइवान और तिब्बत में चीनी चिंताओं के प्रति संवदेनशील है, उसी प्रकार चीन जम्मू–कश्मीर में हमारी चिंताओं के प्रति संवेदनशील बने। दूसरी तरफ यांग ने यह संकेत देने का प्रयास किया कि चीन इस पर निष्पक्ष रुख अपना रहा है और भारत–एवं पाकिस्तान को इस मसले को वार्ता से सुलझाना चाहिए। भारत अक्सर चीन द्वारा दुहराए जाने वाले इस पक्ष पर हमेशा सवालिया निशान लगाता रहा है क्योंकि पहली बात तो यह है कि इस दावे की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है और दूसरी बात यह है कि चीन–पाक की दोस्ती एक ऐसे अलग तरह के स्तर तक पहुंच चुकी है जहां ऐसे सवाल काफी हद तक अप्रासंगिक रह जाते हैं।

चीन के कदमों पर भारत की है 'लगातार नजर': एस. एम. कृष्णा

(फायूल, 11 नवंबर)

भारत ने कहा है कि वह चीन के उन सभी विकास परियोजनाओं पर 'लगातार नजर' बनाए हुए है जिनका भारत की सुरक्षा पर कोई असर हो सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने लोकसभा को बताया कि तिब्बत और शिनजांग सहित अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन द्वारा रेलमार्ग के विकास के बारे में भारत को जानकारी है।

लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में कृष्णा ने कहा, "चीनी सीमा के समानांतर अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है ताकि अपनी सामरिक और सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति हो सके और इन इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। इनमें जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि भारत इस बात से भी वाकिफ है कि विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तैयार करने के लिए चीन ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाए हैं। हाल में यह खबरें मिली हैं कि कोलंबो साउथ कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए एक चीनी कंपनी ने श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। चीन और भारत कई मसलों पर उलझते रहे हैं। चीन ने पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा की यात्रा पर आपत्ति की थी। चीन भारत के इस उत्तर–पूर्वी राज्य को 'दक्षिणी तिब्बत' का हिस्सा मानता है। भारत ने चीन की इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा था कि तिब्बती नेता दलाई लामा उसके 'सम्मानित अतिथि' हैं और वे भारत में कहीं भी यात्रा करने के लिए आज़ाद हैं।

चीन ने अपने पंजे फैलाए, एशिया पर डाली अपनी छाया

(डीएनए, मुंबई, 1 अक्टूबर)

प्रोफेसर ब्रह्मा चेलानी

चीन के मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर के कप्तान को रिहा करके जापान ने यह छवि बनाई है कि वह पूरी तरह चीन के दबाव में आ चुका है। लेकिन जापान के इस कार्य से चीन पर भी रोशनी पड़ती है, जिसकी तेजी से बढ़ती ताकत ने उसको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वह जापान से लेकर भारत तक अपने पड़ोसियों के क्षेत्रीय और समुद्री इलाकों पर दावा कर सके। अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद में चीन की नई तीक्ष्णता से एशिया की इस केंद्रीय चुनौती को समझने में मदद मिलती है जिसमें इतिहास के बोझ से छुटकारा पाकर मौजूदा सीमाओं पर बातचीत की जाती है। एशिया आर्थिक रूप से एक–दूसरे पर ज्यादा निर्भर हो रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह ज्यादा विभाजित होता जा रहा है। 20वीं शताब्दी के पहले पचास सालों में हुए खूनी युद्धों के बाद अब यूरोप युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन एशिया में 20वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में हुए युद्धों से मसले सुलझ नहीं पाए और इससे केवल कड़वी दुश्मनी और बढ़ गई। 1950 से ही एशिया के कई राष्ट्रों में युद्ध होते देखे गए, 1950 में ही कोरियाई युद्ध और तिब्बत को हड़पने की प्रक्रिया शुरू हुई। इन युद्धों से विवाद हल होने या खत्म होने की जगह केवल अस्थायी रूप से रुक गए।

एक मजबूत और ज्यादा संपन्न चीन अपने पड़ोसियों के प्रति ज्यादा दबंग विदेशी नीति को अपनाना शुरू कर चुका है, इसका उदाहरण इस साल होने वाली कई घटनाओं में देखा जा सकता है।

आज चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो या ताइवान या सेनकाकु द्वीप या स्पाटर्ली द्वीप, चीन अपने दावों के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की धमकी का सहारा ले रहा है। ऐसा करके चीन ने चीनी खतरे के साए को और मजबूत किया है। अपने पड़ोसियों को सीमाओं की लड़ाइयों मे उलझाकर चीन एशिया के मौजूदा आर्थिक पुनर्जागरण को भी खतरे में डाल रहा है।

चीन सबसे ज्यादा सैन्य युद्धों में शामिल रहा। पेंटागन की एक हालिया रिपोर्ट से यह उदाहरण मिलता है कि किस प्रकार चीन ने सामरिक सुरक्षा के नाम पर 1950, 1962 और 1969 में पहले लड़ाई छेड़ी। 1974 में चीनी सैनिकों द्वारा वियतनाम से पैरासेल द्वीप को छीन लेना इस बात का एक और उदाहरण था कि वह आक्रमण को ही सुरक्षा मानता है। लड़ाइयां शुरू करने के ये सारे मामले तब के हैं जब चीन कमजोर, गरीब और आंतरिक रूप से परेशान था। इसलिए आज चीन की बढ़ती ताकत स्वाभाविक रूप से वैधानिक चिंताओं को जन्म देती है।

एक मजबूत और ज्यादा संपन्न चीन अपने पड़ोसियों के प्रति ज्यादा दबंग विदेशी नीति को अपनाना शुरू कर चुका है, इसका उदाहरण इस साल होने वाली कई घटनाओं में देखा जा सकता है। इसने दक्षिण चीन सागर को अपने 'मुख्य' राष्ट्रीय हितों में शामिल किया है, यह एक ऐसा कदम है जिससे विवादास्पद स्पार्टली द्वीपों पर उसके दावे पर अब बातचीत मुश्किल है, इसने येलो सी को एक विशेष चीनी सैन्य अभियान क्षेत्र के रूप दर्शाया है जहां वह अमेरिका एवं उत्तर कोरिया को संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नहीं करने देगा। चीन ने जापान नियंत्रित सेनकाकु द्वीपों को अपना क्षेत्र बताने का दबाव बढ़ाया है और चीनी युद्धक जहाजों का जापानी समुद्री सीमा में अतिक्रमण बढ़ गया है। अप्रैल के बाद अब तक चीन ने तीन अलग–अलग बड़े पैमाने के नौसैनिक अभ्यास किए हैं।

तिब्बत में आधिकारिक पीएलए डेली की रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीनों में कई नई और महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधियां हुई हैं, जिनमें पहला बड़ा पैराशूट अभ्यास शामिल है जिसके द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे पठार पर तेजी से सैनिकों को उतारने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। इसके अलावा सैनिकों ने तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का भी अभ्यास किया है जिनसे जिंदा गोला–बारूद ढोए जा सकते हैं।

इसके अलावा तिब्बत तक बना रेलमार्ग जो दुनिया का सबसे ऊंचा एलीवेटेड रेलमार्ग है, अब वहां वायु सेना को लड़ाई के लिए तैयार करने वाले साजो–सामान की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होने लगा है। इन सैन्य गतिविधियों को साल 2006 के बाद चीन के उस रूप के नए उभार के संदर्भ में देखना होगा जिसमें वह उत्तर–पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है और हाल में उसने जम्मू–कश्मीर पर भारत की प्रभुसत्ता पर सवाल उठाए हैं। कश्मीर का करीब 20 फीसदी हिस्सा चीन के कब्जे में है। इस पृष्ठभूमि में चीन के लगातार बढ़ते क्षेत्रीय और समुद्री सीमा पर दावे एशिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा हैं। वास्तव में चीन की जिस सबसे बड़ी जमीन पर लोभी नजरें हैं वह दक्षिण या पूर्वी चीन सागर में नहीं बल्कि भारत में है, उसकी नजर अरुणाचल प्रदेश पर है जो ताइवान से तीन गुना बड़ा है।

किसी भी महाद्वीप में शांति और स्थिरता की पूर्व शर्त यही है कि सभी देश एक–दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। यूरोप ने इसी सिद्धांत पर शांति कायम की है और बहुत से यूरोपीय देशों ने उन सीमाओं के साथ भी जीना सीख लिया है जो उन्हें पसंद नहीं हैं। क्षेत्रीय और समुद्री सीमाओं का नया नक्शा बनाने का प्रयास एशिया में युद्धों का बढ़ावा देने का आमंत्रण जैसा है। क्षेत्रीय यथास्थिति को अस्वीकार कर चीन ने राजनीतिक संवाद की निरर्थकता को ही रेखांकित किया है। आखिरकार सीमाओं के नक्शे में बड़ा फेरबदल कभी भी वार्ता की मेज पर नहीं हुआ। इस प्रकार का नया मानचित्रण केवल युद्ध के मैदान में ही किया जा सकता है जैसा कि चीन इतिहास में कर चुका है।

आज चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो या ताइवान या सेनकाकु द्वीप या स्पाटर्ली द्वीप, चीन अपने दावों के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की धमकी का सहारा ले रहा है। ऐसा करके चीन ने चीनी खतरे के साए को और मजबूत किया है। अपने पड़ोसियों को सीमाओं की लड़ाइयों मे उलझाकर चीन एशिया के मौजूदा आर्थिक पुनर्जागरण को भी खतरे में डाल रहा है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने यह दिखाया है कि वह एशिया का नेतृत्व करने के लिए भरोसेमंद उम्मीदवार नहीं है। नेतृत्व सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दूसरे देशों की रजामंदी या

मौन स्वीकार्यता से ही मिल सकता है। दूसरे एशियाई देशों और शेष अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बीजिंग को एक साफ संकेत दें। छह लंबे दशकों के बाद अब चीन द्वारा सीमाओं में फेरबदल का प्रयास बंद होना चाहिए।

चीन को भारत के साथ बड़ी समस्या है

(यूरेसिया रीव्यू, 27 नवंबर)

भास्कर राय

भारतीय सेना के दो पर्वतीय डिवीजन को अरुणाचल प्रदेश में तैनात करने और उसके अगले साल तक पूरी तरह सक्रिय हो जाने की खबर से ऐसा लगता है कि चीन सरकार को बहुत अधिक परेशानी हो रही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मा झाजू ने भारत को चीन की चिंता का ध्यान रखने का सुझाव दिया है और क्षेत्र में अस्थिरता पैदा नहीं करने का सुझाव दिया है, जिससे चीन और भारत के स्वास्थ्य संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

चीन के अंग्रेजी भाषा के सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' के 23 नवंबर को भारतीय मीडिया में इन खबरों के छपने की मंशा पर सवाल उठाया गया, क्योंकि दिसंबर में चीन के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर जाने वाले हैं। ग्लोबल टाइम्स कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र 'दि पीपुल्स डेली' का सहायक अखबार है। इसे चीन सरकार के आधिकारिक विचारों का प्रामाणिक अखबार माना जाता है। शंघाई इंटरनेशनल स्टडी के भारत संबंधी मामलों के विशेषज्ञ वांग देहुआ का मानना है कि भारत 29 और 30 नवंबर को बीजिंग में सीमा विवाद पर होने वाली भारत–चीन वार्ता से पहले अपने हाथ मजबूत करना चाहता है। उधर चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में एशिया–प्रशांत अध्ययन के विशेषज्ञ सन शिहाई का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में बढ़ाई गई सैन्य क्षमता से पता चलता है कि भारत सीमा वार्ता पर कोई लचीलापन नहीं दिखलाना चाहता है।

रोचक बात यह है कि ग्लोबल टाइम्स ने यह याद दिलाने की कोशिश की कि चीन के विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर, 2009 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अरुणाचल प्रदेश यात्रा की भर्त्सना की थी। कट्टर राष्ट्रवादी विचारों के लिए जाने जाने वाले इस अखबार ने हालांकि उसके बाद क्या हुआ था यह याद करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की इसी से यह पता चलता है कि यह क्षेत्र विवादित नहीं है। यही नहीं उसके बाद चीनी प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों में नरमी लाने के लिए थाइलैंड में हो रहे एक सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री को मुलाकात के लिए भी आमंत्रित किया था। यह आश्चर्यजनक है कि छह दशकों के द्विपक्षीय संबंध के बाद भी चीन यह नहीं समझ पाया है कि भारत किस तरह से काम करता है। या नहीं तो भारतीय मीडिया में छपी खबरों के आधार पर भारत की आलोचना करना सिर्फ एक दबाव बनाने की राजनीति हो सकती है। चीन की सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि भारत में सरकार संसद और आम जनता के प्रति जवाबदेह है। इसलिए कोई भी काम हो, चाहे वह सेना की तैनाती भी क्यों न हो, भारत सरकार को पारदर्शी तरीके से आम जनता को बताना पड़ता है। उधर चीन में ऐसा नहीं है। वहां सरकार आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और मीडिया संवैधानिक रूप से सरकार के नियंत्रण में है।

जहां चीनी और भारतीय नेता तनाव को कम से कम करने, द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग का विस्तार करने के लिए सहमत हुए हैं, वहीं चीन के कुछ ताकतवर नेता इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो भला क्यों चीनी विदेश मंत्रालय सीमा वार्ता से पहले और चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से पहले भारत को चेतावनी देता। अगर ऐसा नहीं है, तो भला क्यों ग्लोबल टाइम्स लगातार अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा कहता।

दक्षिणी तिब्बत जैसे शब्द का कोई इतिहास नहीं रहा है। पिछले दो सालों से इस शब्द को गढ़कर अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई सिर्फ इतनी है

इसके हालिया उदाहरण के तौर पर उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को चीन आने के लिए नत्थी किया हुआ वीजा देना शुरू किया है, पाकिस्तान के कब्जाए कश्मीर को पाकिस्तान की पूर्ण संप्रभुता वाला क्षेत्र और भारतीय कश्मीर को विवादित क्षेत्र कहना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उसने कश्मीर को चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच त्रिपक्षीय मसला कहना शुरू कर दिया है।

एशिया के दो सबसे बड़े देशों को जहां दोनों देशों के लिए समान मुद्दों और इस क्षेत्र के विकास पर मिलकर काम करना चाहिए, वहीं चीन के व्यवहार से भरोसे का माहौल नहीं बन पा रहा है। भारत ने प्रयोग के तौर पर तेल एवं गैस के लिए चीन के साथ मिलकर बोली लगाई, लेकिन एक दिन सुबह भारत को पता चला कि चीन ने रात में ही उसे धोखा दे दिया।

कि छठे दलाई लामा का तवांग में जन्म हुआ था, लेकिन इससे कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। दलाई लामा या तिब्बती समुदाय का कोई भी धार्मिक नेता दुनिया में कहीं भी जन्म ले सकता है।

हाल में प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपी चीन की आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट या अध्ययन को पढ़ने से स्पष्ट पता चलता है कि विदेश नीति के मसले पर चीन के शीर्ष नेतृत्व में दो तरह के विचार हैं। चीन के पड़ोसियों के साथ हठधर्मीपूर्ण रवैये की वैश्विक स्तर पर हो रही आलोचना के बाद ऐसा लगता है कि पार्टी की केंद्रीय समिति ने अड़ियल रवैया त्याग दिया है, लेकिन देश पहले से स्थापित विचारों पर कायम है। फिर भी सैन्य झुकाव रखने वाला एक खेमा देश से बाहर सैन्य हस्तक्षेप की प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर पाया है। चीन के राष्ट्रपति और पार्टी के महासचिव हू चिंताओ इस स्थिति में नहीं हैं कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को पूरी तरह नियंत्रित कर सकें। पीएलए सुरक्षा, पड़ोसी और अमेरिका संबंधी मामलों को बहुत अधिक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हू चिंताओ को अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए पीएलए की बात माननी पड़ती है, चाहे वे भले ही खुद वैसा करना नहीं चाहते हों। देंग शियोपिंग पीएलए को नियंत्रित रखने वाले अंतिम चीनी नेता थे।

जैसे–जैसे चीन आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत होता गया, इसने भारत की संप्रभुता और सीमा सुरक्षा को चोट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के साथ एक समीकरण विकसित कर लिया। इसके हालिया उदाहरण के तौर पर उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को चीन आने के लिए नत्थी किया हुआ वीजा देना शुरू किया है, पाकिस्तान के कब्जाए कश्मीर को पाकिस्तान की पूर्ण संप्रभुता वाला क्षेत्र और भारतीय कश्मीर को विवादित क्षेत्र कहना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उसने कश्मीर को चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच त्रिपक्षीय मसला कहना शुरू कर दिया है।

चीन भारत को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह छोटा–मोटा मुद्दा है, भारत इस पर अधिक ध्यान न दे, बल्कि जलवायु परिवर्तन और पश्चिम के खिलाफ मुद्रा के मुल्य जैसे मुद्दों पर सहयोग करे। एशिया के दो सबसे बड़े देशों को जहां दोनों देशों के लिए समान मुद्दों और इस क्षेत्र के विकास पर मिलकर काम करना चाहिए, वहीं चीन के व्यवहार से भरोसे का माहौल नहीं बन पा रहा है। भारत ने प्रयोग के तौर पर तेल एवं गैस के लिए चीन के साथ मिलकर बोली लगाई, लेकिन एक दिन सुबह भारत को पता चला कि चीन ने रात में ही उसे धोखा दे दिया। भौगोलिक स्थिति दोनों देशों को मिलकर काम करने और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए बाध्य करती है। अभी तक हालांकि चीन ने अपनी विश्वसनीयता का कोई संकेत नहीं दिया है। इधर भारत में लोगों को लगने लगा है कि चीन के दोयम व्यवहारों की अब हद हो चुकी है। उधर बीजिंग को भी यह समझ लेना चाहिए कि भले ही वह परमाण्विक और सैन्य क्षमता में आगे है, लेकिन आज 1962 वाली स्थिति नहीं है। चीन का स्वागत तभी हो सकता है जब वह दिखाए कि वह वाकई विकास का साझीदार है। अभी तक हालांकि यह नहीं हुआ है। मध्य दिसंबर में भारत आ रहे चीनी प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ वस्तुतः एक निष्प्रभावी प्रधानमंत्री हैं। पिछले दिनों चीन के आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक माहौल बनाने की बात करने के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया। अक्टूबर में पार्टी अधिवेशन में उनकी आवाज दब गई। कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें किनारे कर दिया गया। अगले दो साल तक वे पद पर बने जरूर रहेंगे, लेकिन उतना ही कर पाएंगे, जितना पार्टी की ओर से उन्हें बताया जाएगा। वेन च्यापाओ की भारत यात्रा से कुछ अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती। वे भारत और पाकिस्तान में सिर्फ पहले से तय बातों को ही दोहराएंगे। लेकिन भारत इस अवसर का लाभ बिना किसी मुश्किल के अपने पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। भारत के लिए यह स्पष्ट करने का बेहतरीन अवसर है कि भारत के लिए बड़ा मुद्दा क्या है और छोटा मुद्दा क्या है।